तिब्बत देश

चीन के खिलाफ पानी के लिए युद्ध संभव

तिब्बत में जलस्रोतों पर चीन की सरकार सुनियोजित तरीके से अपने नियंत्रण को मजबूत करती जा रही है तथा जल प्रबंधन में पर्यावरण, प्रकृति एवं मानवीय हितों की उपेक्षा कर रही है। यह पूरे विश्व के लिए, विशेषकर एशियाई देशों के लिए, गंभीर जल–संकट पैदा करने वाला है। चीन के इन प्रयासों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सबको एकजूट होना होगा। यह केवल तिब्बत के भविष्य, और यहां तक कि उसके वर्तमान से भी, खिलवाड़ नहीं है। चीन द्वारा तिब्बत में जल–नियत्रंण एवं प्रबंधन का तरीका चीन के लिए भी अहितकर साबित होगा।

अपनी भोगवादी जीवन शैली के कारण चीन पर्यावरण–आवश्यकताओं की अनदेखी करके उद्योग एवं कृषि का विकास कर रहा है। वह वनों की कटाई कर रहा है। तिब्बत में खनिज पदार्थों को अंधाधुंध निकाल रहा है। प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण को उजाड़ते हुए उसने ल्हासा तक रेलमार्ग का विस्तार कर लिया है और तिब्बत में सड़कों का अनावश्यक जाल बिछा रहा है। तिब्बत में तिब्बती ही अल्पसंख्यक हो जायेंगे, क्योंकि वहां चीनी लोगों को बसाया जा रहा है। तिब्बती स्वभावतः भगवान् बुद्ध के दर्शन के अनुरूप प्रकृति एवं पर्यावरण का संरक्षण करने वाले होते हैं। इसके ठीक विपरीत मार्क्स–माओ के अनुयायी साम्यवादी चीनी स्वभावतः भोगवादी और साम्राज्यवादी हैं।

चीन की तिब्बत में जारी जल नीति का नतीजा है कि भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन तथा तुर्किस्तान से सटे तिब्बत में ग्लेशियर सूखते जा रहे हैं। कुछ इलाकों में प्रतिवर्ष तीन फीट से भी ज्यादा की दर से ग्लेशियर सिकुड़ने लगे हैं। चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्जा जमा रखा है। वह तिब्बत का हर तरह से विनाश कर रहा है। वहां लूट–खसोट कर रहा है। वहां मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। और अपने लिए तिब्बत से स्वच्छ एवं पर्याप्त पानी का इंतजाम करने में लगा है। अनेक शोध–निष्कर्षों के अनुसार चीन की सत्तर प्रतिशत नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं।

चीन द्वारा तिब्बत की बड़ी नदियों येलो, यार्लुंग त्सांग्पो, यांगत्से, मेकोंग, साल्वीन तथा सतलज आदि पर बड़े–बड़े बांध बनाये जा रहे हैं। यार्लुंग त्सांग्पो नदी को ही सियांग या ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। वह बड़ी–बड़ी नहरें बना रहा है। खेती और उद्योग की जरूरत पूरी करने के लिए चीन के उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र की ओर नदियों के मार्ग को मोड़ रहा है। ध्यातव्य है कि एक चौथाई चीन मरूभूमि है। लेकिन चीन की गलत नीतियों का नतीजा है कि चीन में और अब तिब्बत में भी पीने लायक पानी कम हो गया है।

अनेक शोधों से पता चला है कि चीन की गलत नीति के कारण संपूर्ण एशिया में स्थित गंभीर हो जायेगी। पानी के लिए इस क्षेत्र में हिंसक संघर्ष होंगे। विश्व की लगभग आधी आबादी तिब्बत के जलस्रोतों पर निर्भर है। निर्वासित तिब्बती सरकार प्रारंभ से ही इस विषय पर अधिकाधिक शोध–अनुसंधान हेतु जोर दे रही है। तभी पता चलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग की तरह ही तिब्बत में जारी चीन की जल–नीति भी ग्लेशियरों के लिए खतरा है। दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा केवल तिब्बत में ही जीवनदायी जल–स्रोत मौजूद हैं। अकेले तिब्बत में ही एक हजार से ज्यादा स्वच्छ जल की झीलें हैं। लेकिन चीन की नीति दो–तीन दशकों में ही इन्हें सूखा देगी।

तिब्बत का पानी चीन के लिए जीवन–मरण का प्रश्न बन गया है। यही कारण है कि चीन की सरकार विशेषज्ञों के सुझावों एवं विश्लेषण की जानबूझकर उपेक्षा कर रही है। इंटर गवर्नमेंटल पैनेल ऑन क्लाइमेट चेंज समेत अनेक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन चेतावनी दे रहे हैं कि चीन का तिब्बत में जल–प्रबंधन का तरीका दोषपूर्ण है। इन तथ्यों की जानकारी चीन के विशेषज्ञों तथा शोध संस्थानों को भी है। किन्तु साम्यवादी सरकार के भय से वे सच को सामने नहीं ला रहे हैं। फिर भी सच को ज्यादा समय तक छिपाया नहीं जा सकता। चीन के सभी पड़ोसी पानी के लिए तरसेंगे और तड़पेंगे। चीन की नीति पड़ोसी देशों में कभी सूखे से तो कभी बाढ़ से बर्बादी लाएगी। तिब्बत की कई नदियां अन्य कई देशों में भी बहती हैं। इन पर बांध बनाकर चीन उन देशों को बर्बाद करने पर तुला है। इससे इस क्षेत्र में पानी के लिए युद्ध का माहौल तैयार होने लगा है।

अस्वच्छ जल के कारण तिब्बत के पड़ोसी देशों में कई बीमारियां फैलने लगी हैं। तिब्बत में भी ऐसा हो रहा है। स्वच्छ पानी कम हो रहा है, क्योंकि वाष्पीकरण की गति बढ़ती ही जा रही है। चीन की गलत नीति से गर्मी बढ़ रही है और वाष्पीकरण इसी का नतीजा है।

अभी 10 दिसंबर 2012 को विश्वस्तर पर तिब्बतियों एवं तिब्बत समर्थकों द्वारा ग्लोबल सॉलिडरिटी डे का आयोजन किया गया। इसकी अपील निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे ने की थी। इस अवसर पर उम्मीद जाहिर की गई है कि चीन के नए राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा प्रधानमंत्री ली कीखेयंग वेन जियाबाओ स्थिति की गंभीरता को समझेंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति, विशेषकर एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, तिब्बत के अंदर ग्लेशियरों तथा अन्य सभी जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठायेंगे।

प्रो0 श्यामनाथ मिश्र

पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी (राज.)मो.–9829806065, 8764060406 E-mail & facebook: shyamnathji@gmail.com

तिब्बती अधिकारों के उल्लंघन की आवाज भारतीय संसद में गूंजी

(फायूल, 10 दिसंबर, 2012)

तिब्बत के भीतर जारी संकट की गूंज सोमवार, 10 दिसंबर को भारतीय संसद में भी सुनाई दी। कई वरिष्ठ नेताओं ने संसद से तिब्बत पर "आवाज़ उठाने" को कहा। भाजपा नेता और पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने तिब्बत के भीतर के गंभीर हालात पर बोलते हुए चीन पर यह आरोप लगाया कि वह पिछले 60 वर्ष में तिब्बत के भीतर मानवाधिकारों का "घोर" उल्लंघन कर रहा है. वह संसद के निचले सदन लोकसभा में शून्य काल में बोल रहे थे।

सिन्हा ने कहा, "तिब्बत के भीतर आत्मदाह की चल रही लहर चीन द्वारा उस इलाके में सैन्य ताकत के बहुत ज्यादा इस्तेमाल, धार्मिक प्रतिबंध, लोगों को गायब कर देने और जेल में बंद करने, नोमैड को उनकी जगह से हटाने और पारिस्थितिक तंत्र की दुर्दशा करने का नतीजा है।" पूर्व भारतीय विदेश मंत्री ने कहा, "बदतर यह है कि इसकी प्रतिक्रिया होने पर चीन और दमन करता है।" उन्होंने भारतीय संसद से आग्रह किया कि वह तिब्बतियों की दुर्दशा पर "गहरी हार्दिक संवेदना" जताए और चीन से यह आग्रह करे कि वह "वेदना को सुने और यह सुनिश्चित करे कि लोगों (तिब्बत के) को उनके अधिकार मिलें।" उन्होंने निवेदन करते हुए कहा, "मैं संसद से आह्वान करता हूं कि वह कुछ बोले।"

इसके पहले सिन्हा ने तिब्बत पर सर्वदलीय संसदीय मंच के अध्यक्ष की हैसियत से इस साल सितंबर माह में निर्वासित तिब्बती सरकार के धर्मशाला स्थित मुख्यालय का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई थी कि भारत अपनी तिब्बत नीति में "समयानुकूल बदलाव" करेगा। अपने तीन दिवसीय दौरे के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा था, "मुझे उम्मीद है कि भविष्य में समयानुकूल बदलाव होगा और तिब्बत के हित के लिए भारत ज्यादा मजबूती से खड़ा होगा। चीन को भारत बहुत साफ शब्दों में बता देगा कि नरसंहार, नस्ल की सफाई और तिब्बती सभ्यता का पूरी तरह से विनाश भारत को मंजूर नहीं होगा।"

आत्मदाह की लहर के बारे में सिन्हा ने कहा कि "तिब्बत में चीन दमन की सारी सीमाएं पार कर रहा है।" उन्होंने कहा, "किसी की हत्या करना संभवतः खुद को जलाने से आसान है। तिब्बत में आत्मदाह की लहर यह दिखाती है कि तिब्बत में दमन की सारी सीमाएं पार हो गई हैं।"

तिब्बतविदों ने तिब्बती संस्कृति को बचाने के लिए शी जिनपिंग से निवेदन किया

(डिडी क्रिस्टेन टैटलो। न्यूयॉर्क टाइम्स बीजिंग, 15 दिसंबर, 2012)

मेलबोर्न से लेकर वारसा और वैंकुअर तक दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और संस्थाओं ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नए नेता से निवेदन किया है कि वे सरकार की उन भाषाई नीतियों और चलन को बदलें जिनसे "तिब्बती सभ्यता के अस्तित्व पर लगातार जोखिम बना हुआ है"। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इससे तिब्बत में चीनी शासन के प्रति असंतोष बढ़ रहा है। तिब्बत में बढ़ते आत्मदाह (मेरे सहयोगी एंड्रयू जैकब की खबर के अनुसार फरवरी, 2009 से अब तक करीब 100 मामले) के खिलाफ कई ऐसे विद्वानों ने एक ऑनलाइन याचिका की शुरुआत की है। "तिब्बत का अध्ययन करने वाले अंतरराष्ट्रीय समुदाय की तरफ से उप राष्ट्रपति शी जिनपिंग से एक निवेदन" शीर्षक वाले इस याचिका में आत्मदाह पर फोकस तो नहीं किया गया है, लेकिन इसमें "हो रही दुःखद घटनाओं का उल्लेख किया गया है।"

ये सभी विद्वान तिब्बती भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेषज्ञ हैं जो विभिन्न औपचारिक अकादमिक पदों पर हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसी भाषाई नीतियों पर फोकस किया है जिनसे उनके मुताबिक तिब्बती संस्कृति को खतरा हो रहा है।

उन्होंने लिखा है, "पिछले कई वर्षों से प्रशासन के लोग ऐसे नए–नए उपाय लागू करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे तिब्बती बोलने वाले इलाकों में पढ़ाई के माध्यम के रूप में तिब्बती का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा या बुरी तरह प्रतिबंधित हो जाएगा।"

इसमें लिखा गया है, "हम तिब्बती सभ्यता का महत्व जानते हैं और हमें दुःख है कि टीएआर (यानि तिब्बती स्वायत्तशासी क्षेत्र, चीन में तिब्बत को इसी नाम से जाना जाता है) और अन्य तिब्बत स्वायत्तशासी प्रशासनिक इकाइयों में इस सभ्यता के बुनियादी आधार तिब्बती भाषा को हाशिए पर धकेला जा रहा है, जबकि दुनिया के अन्य हिस्सों के विश्वविद्यालयों में तिब्बती भाषा को पढ़ने–पढ़ाने का सिलसिला बढ़ रहा है।

याचिका में जिन मामलों का उदाहरण दिया गया है उनमेंः वर्ष 2010 में क्विंघई प्रांत में पढ़ाई के माध्यम के रूप में तिब्बती को हटाकर चीनी भाषा को लाने और मार्च 2012 में क्विंघई प्रांत के टोंगरेन काउंटी या रेबकोंग में तिब्बती भाषा की पुस्तकों को हटाकर चीनी भाषा की पुस्तकों को

लागू करना शामिल हैं। विद्वानों ने कहा, "यह नीति तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में पिछले कई साल से सक्रियता से लागू है और इसके जाहिर परिणाम हुए हैंः सार्वजनिक या निजी क्षेत्र की नौकरियों को लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा या सभ्यता की बहुत सतही जानकारी है।"

चीन का कहना है कि वह तिब्बत और क्विंघई, गांसू एवं सिचुआन प्रांत में स्थित आसपास के तिब्बती काउंटी में एक "द्विभाषी" शिक्षा नीति का समर्थन करता है और इससे तिब्बतियों और उनके समाज को शिक्षित करने और उन्हें विकसित करने में काफी मदद मिली है। चीन की सरकारी वेबसाइट पर तो तिब्बत पर चीनी नजरिए को ही ज्यादा पेश किया गया है। इस वेबसाइट पर हाल के कार्यक्रमों की जानकारी भी दी गई है। इनमें "स्कूलों, समुदाय और मीडिया में राष्ट्रीय क्षेत्र चेतना शिक्षा" शामिल है जिसको प्रकट तौर पर दिसंबर में शुरू किया गया। इसका लक्ष्य "प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को उनकी पहचान के बारे में जागरूक करना और सचेत तरीके से राष्ट्रीय क्षेत्र के बारे में उनकी चेतना को बनाए रखना" है। भारत में निर्वासित तिब्बतियों द्वारा स्थापित संगठन तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र (टीसीएचआरडी) के अनुसार इस तरह के "देशभक्ति शिक्षा" को लेकर तिब्बत में भारी गुस्सा है। ऐसा लगता है कि इस मसले को लेकर विद्वानों में भारी मतभेद हैं।

मूलतः क्विंघई प्रांत के और अब बीजिंग में रहने वाले एक तिब्बती टाशी (जो सरकारी प्रतिक्रिया की डर से अपना पूरा नाम नहीं बताना चाहते थे) ने कहा कि हाल के दिनों में उनके गृह काउंटी में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना भी कठिन हो गया है क्योंकि इसके लिए जो परीक्षा होती है उसका लिखित हिस्सा सिर्फ चीनी भाषा में उपलब्ध होता है। बहुत से साधारण तिब्बती अच्छी तरह से तिब्बती भाषा लिख या पढ़ नहीं सकते। टाशी ने कहा कि यह आधिकारिक नीति तो नहीं लगती बल्कि यह स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। इससे परेशान लोगों को लाइसेंस हासिल करने के लिए स्थानीय कर्मचारियों को घूस देना पड़ रहा है।

विद्वानों ने शी से अनुरोध किया है कि वह तिब्बतियों को ज्यादा भाषाई और सांस्कृतिक अधिकार दें, जिसकी चीनी संविधान में गारंटी दी गई है। उन्होंने लिखा है, "ऐसे समय में जब नया नेतृत्व देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले रहा है, हम आपसे सामूहिक रूप से मुखातिब हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप चीन में रहने वाले तिब्बती नागरिकों की आकांक्षाओं के प्रति सहानुभूति रखेंगे, आप उनके साथ मिलकर इस समस्या का शांतिपूर्ण हल निकालने की कोशिश करेंगे, आप तिब्बती भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने और उसके विकास की इजाजत देंगे।"

निर्वासित तिब्बती प्रशासन ने ऑनलाइन एकजुटता अभियान की शुरुआत की

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 06 दिसंबर, 2012)

निर्वासित तिब्बती प्रशासन के प्रमुख सिक्योंग लोबसांग सांगे ने 5 दिसंबर को एक ऑनलाइन एकजुटता अभियान शुरू किया। दस दिसंबर पर विशेष रूप से ध्यान दिलाने के लिए पहले से इसे अभियान की शुरुआत की गई। उन्होंने माइक्रोसाइट www.solidaritywithtibet.org और फेसबुक पेज (www.facebook.com/SolidarityWithTibet) की शुरुआत की। इसके बाद धर्मशाला में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, "यह अभियान अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस ध्येय के साथ संगठित करने लिए तैयार किया गया है कि वह तिब्बत के दुखद हालात पर मूकदर्शक न बने रहें, जहां फरवरी, 2009 के बाद चीनी शासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए, दलाई लामा को वापस बुलाने और तिब्बती लोगों को आज़ादी देने की मांग के साथ 92 लोग आत्मदाह कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 में ही 79 लोग आत्मदाह कर चुके हैं जिनमें से अकेले नवंबर, 2012 में ही 28 लोग आत्मदाह कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 10 मार्च, 2012 को तिब्बत जनमत निर्माण वर्ष के रूप में मनाने की उन्होंने जो घोषणा की थी उसको काफी सफलता मिली है। यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली और अमेरिका की संसदों और राष्ट्रीय कांग्रेस ने तिब्बत के बारे में प्रस्ताव पारित किया है। इसी तरह से आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, भारत, जापान, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और कई अन्य देशों की संसदों ने तिब्बतियों के समर्थन में बयान जारी किए हैं।

उन्होंने मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त सुश्री नवी पिल्लई और चीन में अमेरिकी राजदूत श्री गैरी लॉक द्वारा तिब्बत के दुःखद हालात पर हाल में जारी बयानों का भी स्वागत किया। उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल, रिपोटर्स विदाउट बॉर्डर्स, ह्यूमन राइट्स वाच और चीन पर अमेरिकी कांग्रेस के कार्यकारी आयोग जैसे कई संगठनों को तिब्बत पर रिपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया।

दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र से अपील

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 12 दिसंबर, 2012)

तिब्बतियों और उनके अभियान के समर्थकों ने 10 दिसंबर को 64वां विश्व मानवाधिकार दिवस और दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की 23वीं वर्षगांठ मनाया। इस अवसर पर जनसभाओं का आयोजन किया गया और खासकर तिब्बत के भीतर के मौजूदा दुःखद हालात (फरवरी 2009 से अब तक वहां 95 लोग आत्मदाह कर चुके हैं) की जानकारी संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचाने की कोशिश की गई। पूरे भारत में 6 जुलाई, 2012 से और शेष दुनिया में 2 सितंबर, 2012 से भ्रमण कर रहे तीन 'सत्य की ज्वाला' मशालों को न्यूयॉर्क शहर में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त और नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र को सौंपा गया। इसके साथ ही तीनों कार्यालयों पर एक याचिका भी सौंपी गई जिसमें तिब्बत के आज के दुःखद और लगातार बदतर होते जा रहे हालात में संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने की मांग की गई। इन याचिकाओं पर 90 देशों के 3,51,000 से ज्यादा लोगों ने दस्तखत किए हैं।

निर्वासित तिब्बती प्रशासन का आधिकारिक समारोह धर्मशाला के सुगलाकखांग में हुआ जिसके बाद निचले शहर में स्थित जिला अदालत परिसर में एक व्यापक जन विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया और भारत–तिब्बत मैत्री समाज द्वारा एक विशेष शांति प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। तिब्बत के दुःखद हालात को देखते हुए इस साल वार्षिक हिमालय सांस्कृतिक समारोह की जगह प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

इसी तरह कर्नाटक के मुंडगोड के तिब्बती बस्ती में स्थित ड्रेपंग मठ में भी एक बड़ा आयोजन किया गया। इस आयोजन में दलाई लामा ने और सिक्योंग लोबसांग सांगे ने हिस्सा लिया। परमपावन यहां धार्मिक शिक्षण के तहत भ्रमण पर आए हुए थे। सिक्योंग ने घोषणा की कि नई दिल्ली में 30 जनवरी से 2 फरवरी, 2013 तक रैलियों, प्रजेंटेशन और अन्य एकजुटता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसका कशाग और निर्वासित तिब्बती संसद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन किया जाएगा। इसमें तिब्बती प्रशासन के विभिन्न कालोन, निर्वासित तिब्बती सांसद और विभिन्न तिब्बती बस्तियों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

लंदन स्थित 190 तिब्बत संबंधित गैर सरकारी संगठनों के गठबंधन दि इंटरनेशनल तिब्बत नेटवर्क ने एक बयान जारी कर ईयू से कहा है कि वह इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं से "तिब्बत में जारी संकट की स्थिति पर बोलने" को कहे और वे इस पर कुछ सुझाव भी दें। इसमें ईयू से कहा गया है कि वह तिब्बत मसले को हल करने के लिए नई, ज्यादा पुष्ट और समन्वित रणनीति बनाने और उसे लागू करने के लिए संबद्ध देशों के एक संपर्क समूह का गठन करे और उसमें हिस्सा ले।

लंदन में चाइनीज, उइगर ऐंड तिब्बतन सॉलिडरिटी यूके नाम के एक गठबंधन ने एक बयान जारी कर दुनिया के नेताओं से यह आह्वान किया है कि वह चीन सरकार पर इस बात के लिए दबाव डालें कि वह वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य मानव और नागरिक अधिकारों के मानक को स्वीकार करे और कानून के शासन को आगे बढ़ाए। संगठन ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने, खासकर तिब्बत और उइगर इलाकों में मीडिया की स्वतंत्र तरीके से आवाजाही की इजाजत देने, चीन में लोकतंत्र लागू करने, चीन से निपटने की नीतियों में दुनिया भर की सरकारों द्वारा मानवाधिकारों को प्राथमिकता देने और कम्युनिस्ट चीन के शासन में दमित लोगों के लिए वैश्विक स्तर पर सिविल सोसाइटी की एकजुटता का भी आह्वान किया है। न्यूयॉर्क शहर में हजारों तिब्बती नागरिक और उनके समर्थक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने जुटे। "तिब्बत के लिए एकजुटता रैली" में शामिल लोगों ने मैनहटन वेस्ट साइड से नदी के पूर्वी किनारे होते हुए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के उस पार डैग हैमर्स्कजोल्ड प्लाजा तक मार्च किया। वे बार–बार नारे लगा रहे थे, "हम न्याय चाहते हैं, जाग जाओ संयुक्त राष्ट्र"। रायटर्स की 10 दिसंबर को जारी खबर के अनुसार मार्च करने वाले पहले एवेन्यू से दूसरे एवेन्यू तक समूचे डैग प्लाजा में फैल गए।

तिब्बती युवक ने खुद को चाकू मारकर जान दी

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 6 दिसंबर)

ऐसे समय में जब बीजिंग में चीन द्वारा हर पांच साल पर होने वाले 18वें पार्टी कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा था, तिब्बत के गांसू प्रांत के कान्हलो क्षेत्र के सोए शहर में नवंबर के दूसरे हफ्ते में एक तिब्बती युवक ने खुद को चाकू मारकर जान दे दी है। रेडियो फ्री एशिया की 4 दिसंबर की खबर के अनुसार मरने से पहले खून से लथपथ 30 वर्षीय जिग्मे सेतेन ने अपने खून से ही ऊपरी खाग्या स्कूल की दीवार अपना संदेश लिखा। खबर के अनुसार सेतेन ने

दीवार पर लिखा, "तिब्बत आज़ाद है और दलाई लामा को तिब्बत लौटना चाहिए।" इसके बाद तत्काल ही चीनी अधिकारी दौड़ते हुए गए और सेतेन के संदेश को तत्काल मिटा दिया। स्थानीय अधिकारियों ने इस घटना को गलत रूप देते हुए दुष्प्रचार किया कि सेतेन ने शराब के नशे में खुद को चाकू मार लिया और उनकी मौत हो गई।

चीन सरकार द्वारा सूचनाओं और संचार चैनलों पर सख्त नियंत्रण तथा इस इलाके में लगातार आत्मदाह के कई मामलों के बाद लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध की वजह से यह खबर बाहरी दुनिया तक देर से पहुंची। ऊपरी खाग्या स्थानीय सरकार के केंद्र से करीब आधे मील की दूरी पर रहने वाले छुनाक नोमैड समुदाय के एक सदस्य जिग्मे सेतेन अपने पीछे मां, पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं।

आत्मदाह की तैयारी कर रहे पांच तिब्बती पुलिस से बचने की कोशिश करते हुए नदी में डूबे

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 16 दिसंबर, 2012)

चीनी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए भागते हुए पांच तिब्बती नदी में कूद गए और उनकी डूबकर मौत हो गई है। पुलिस इन तिब्बतियों को गिरफ्तार करना चाहती थी। पुलिस का आरोप था कि वे तिब्बती स्वायत्तशासी क्षेत्र ड्रिरु में 9 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर दो अन्य लोगों के साथ मिलकर चीन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए आत्मदाह करने की योजना बना रहे हैं। रेडियो फ्री एशिया की खबर के मुताबिक आत्मदाह की तैयारी कर रहे दो अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उन्हें अज्ञात स्थान पर ले गई है। खबर में एक तिब्बती सूत्र के हवाले से बताया गया है कि ये सभी लोग बालकर कस्बे के निवासी थे और ये लोग सामूहिक आत्मदाह की योजना बना रहे थे। चीनी पुलिस को उनकी योजना की भनक लग गई और वह उनकी गिरफ्तारी के लिए आ रही थी। अपनी जान देने को तैयार ये लोग चीनी पुलिस के सामने समर्पण करने को तैयार नहीं हुए और अपने घर से भाग निकले। अगले दिन हर जगह, सरकारी इमारतों से लेकर घास के मैदानों में चट्टानों तक ऐसे पत्रक चिपकाए गए दिख रहे थे जिसमें तिब्बतियों को आज़ादी देने का आह्वान किया गया था। तिब्बती भाषा में छपे इस पत्रक में कहा गया था, "हम आज़ादी के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं।" इसके अलावा पत्रक में दलाई लामा को निर्वासन से वापस बुलाने, पंचेन लामा को चीन सरकार की हिरासत से रिहा करने और सभी तीनों परंपरागत तिब्बती प्रांतो को फिर से एक करने की मांग की गई थी।

ड्रिरु में इसके पहले 4 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन करते हुए एक युवक द्वारा आत्मदाह की घटना देखी गई थी। यह युवक शहीद हो गए और उन्होंने एक पत्र लिख छोड़ा था जिसमें तिब्बतियों में एकता और जुटता का आह्वान करते हुए उनसे अनुरोध किया गया था कि वे साहस के साथ अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करें।

ड्रिरु ने हाल के वर्षों में प्रशासन द्वारा कई बार धार्मिक दमन के मामले सामने आए हैं। काफी पीड़ा पहुंचाने वाले तथाकथित देशभक्तिपूर्ण शिक्षा को थोपा गया है, भिक्षुओं को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें मठों से निकाला गया है और कई बार तो मठों को ही बंद कर दिया गया है।

आम तिब्बतियों की भी कई बार गिरफ्तारी की घटनाएं हुई हैं और तिब्बतियों तथा चीनी प्रवासियों के बीच कोई विवाद होने पर पुलिस तिब्बतियों के साथ भेदभाव करती है।

तिब्बत में आत्मदाह की घटना के बाद स्थानीय धार्मिक नेताओं को पकड़ा गया

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 14 दिसंबर, 2012)

आत्मदाह की जारी लहर पर किसी को बलि का बकरा बनाने के भारी दबाव, आत्मदाह करने वाले तिब्बतियों की शिकायतों का समाधान न करने के अपने निश्चय की वजह से क्विंघई प्रांत के डोकर्मो के चीनी अधिकारियों ने 9 दिसंबर को एक स्कूली छात्रा के आत्मदाह करने और उसकी मौत हो जाने के बाद पांच स्थानीय धार्मिक हस्तियों को गिरफ्तार किया है।

रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट के अनुसार 17 वर्षीय स्कूली छात्रा भेनछेन क्यी की 12 दिसंबर को मौत के बाद जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें स्थानीय दोर्जे जोंग मठ के 49 वर्ष के प्रमुख अकु सोंद्रु और 47 वर्ष के तांत्रिक चकथाब शामिल हैं। इनके अलावा तीस के आसपास की उम्र के एक स्थानीय धार्मिक केंद्र के प्रमुख शावो को भी हिरासत में ले लिया गया। इनके अलावा गिरफ्तार दो अन्य लोगों में एक स्थानीय भिक्षुणी मठ की अनुशासन प्रमुख छोड्रोन और एक अन्य महिला रिग्शे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रिग्शे उस 17 वर्षीय भिक्षुणी सांग्ये डोलमा

की बहन हैं जिन्होंने उसी स्थान पर 25 नवंबर को आत्मदाह कर लिया था। प्रशासन ने उस स्कूल को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया है जहां की छात्रा ने आत्मदाह किया है। यह गिरफ्तारियां चीन द्वारा एक नया रेगुलेशन तैयार करने के बाद की गई हैं। इस रेगुलेशन का प्रारूप चीन के जनसुरक्षा मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय पुलिस विभाग ने किया है। इस रेगुलेशन में कहा गया है कि जो लोग आत्मदाह की योजना बनाने, उसके लिए दूसरों को संगठित करने, उकसाने या उनकी किसी तरह की मदद करने में लिप्त पाए जाएंगे उन पर अंतरराष्ट्रीय नर हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा। जो लोग ऐसे आत्मदाह को रोकने के लिए सक्रियता से काम नहीं करेंगे, बस इसको देखते रहेंगे और सड़कों पर लाश को लेकर परेड निकालेंगे, उन पर भी आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा।

इसके पहले, चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ ने 9 दिसंबर को यह खबर दी थी कि सिचुआन प्रांत के अबा प्रशासनिक क्षेत्र में स्थित कीर्ति मठ में 40 वर्ष के एक भिक्षु लोरांग कोनछोक को उनके 31 वर्षीय भांजे लोरांग के साथ गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर 2009 से अब तक आठ लोगों को आत्मदाह करने के लिए उकसाने का आरोप है। खबर के अनुसार आत्मदाह करने वाले इन आठ लोगों में से तीन की मौत हो चुकी है, जिसके बाद उक्त लोगों पर नया रेगुलेशन लागू किया गया है।

चीन ने तिब्बती आत्मदाह पर अंकुश के लिए कानून बनाया

(पीटीआई, 11 दिसंबर, बीजिंग)

तिब्बत में आत्मदाह के सिलसिले में कोई कमी नहीं आ रही है, इसे देखते हुए चीन एक नया कानून लेकर आया है जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति किसी आत्मदाह करने वाले की मदद करता पकड़ा जाता है तो उसे "अंतरराष्ट्रीय नरहत्या" का दोषी माना जाएगा।

सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक जनसुरक्षा और न्यायिक निकाय मंत्रालय द्वारा हाल में तैयार एक कानून के प्रारूप के अनुसार जो लोग दूसरे लोगों की आत्मदाह की योजना बनाने, उसे कारगर बनाने, उकसाने या मदद करने में शामिल पाए जाएंगे उन पर अंतरराष्ट्रीय नरहत्या का मुकदमा चलाया जाएगा। इसके मुताबिक, "जो लोग सड़क पर शव को लेकर जुलूस निकालेंगे या आत्मदाह को देखने के लिए जुटे रहेंगे, उसे रोकने के किसी सक्रिय प्रयास के बिना, उन पर भी आपराधिक मामला चलाया जाएगा।"

चीन ने विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए आठ विद्यार्थियों को जेल भेजा, कई अन्य को हिरासत में लिया गया

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 14 दिसंबर, 2012)

चीन के क्विंघई प्रांत के सोल्हो प्रशासनिक क्षेत्र में स्थित चाबछा काउंटी में चीनी अधिकारियों ने आठ तिब्बती विद्यार्थियों को पांच–पांच साल के लिए जेल में डाल दिया है। इन विद्यार्थियों पर 26 नवंबर को एक व्यापक विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आरोप था। ये सभी विद्यार्थी 18 से 23 वर्ष के हैं और अपनी–अपनी कक्षा के मॉनिटर हैं। उनको बिना कोई उचित मुकदमा चलाए 5 दिसंबर को सजा सुना दी गई। इन आठ विद्यार्थियों में राबतेन, वांगडू सेरिंग, जम्पा सेरिंग, छोक्योंग क्याब, सांग्ये धोनडुब, डोला सेरिंग, सेरिंग टाशी और कुनसांग बम शामिल हैं।

गौरतलब है कि 26 नवंबर को हुए विरोध प्रदर्शनों में 1,000 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल थे और इसका नेतृत्व सोल्हो सोरिंग लोबलिंग स्कूल के विद्यार्थियों ने किया था जो कि परंपरागत तिब्बती औषधियों का अध्ययन कराने वाला स्कूल है। अधिकारियों ने स्कूल में एक कथित देशभक्ति वाली पुस्तिका बांटी थी जिसमें तिब्बती भाषा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई थी और तिब्बतियों के आत्मदाह को "मूर्खतापूर्ण" बताकर मजाक उड़ाया गया था। यह तिब्बती विद्यार्थियों को उकसाने के लिए काफी था।

रेडियो फ्री एशिया की 12 दिसंबर की खबर के मुताबिक ऐसा लगता है कि मुकदमे और जेल का सामना करने वाले ये आठ विद्यार्थी अकेले नहीं होंगे, इसी स्कूल के अन्य विद्यार्थियों को भी स्थानीय पुलिस थाने में बुलाकर 7–8 के समूह में बुलाकर पूछताछ किया जा रहा है। खबर में कहा गया है कि चीन की अद्धैसैनिक पुलिस ने माल्हो प्रशासनिक क्षेत्र के एक शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल को भी घेर रखा है और वहां के 18 विद्यार्थियों को हिरासत में ले लिया है।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कैमरन द्वारा दलाई लामा से संपर्क रखने की रोक का मंत्रियों ने विरोध किया

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 4 दिसंबर, 2012)

ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरन ने कम्युनिस्ट चीन सरकार की चापलूसी के लिए इंतहा कर दी है। उन्होंने जून 2012 में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की ब्रिटेन यात्रा के दौरान अपने मंत्रियों को आदेश दिया था कि दलाई लामा से संपर्क करने से बचें। टेलीग्राफ डॉट यूके पर जारी 2 दिसंबर की खबर के अनुसार प्रधानमंत्री के इस आदेश पर दो मंत्री "भड़क" गए थे।

यह पूर्ण प्रतिबंध तब लगाया गया था जब उसी समय चीन सरकार और जी–20 के देशों के बीच कानकुन, मैक्सिको में यूरो राहत पैकेज की संभावना पर बातचीत चल रही थी। चीन यूरो संकट से निपटने के लिए बनने वाले एक फंड में 27 अरब डॉलर का योगदान देने के बारे में बात कर रहा था। इस फंड का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए करना था। कैमरन सरकार के दो मंत्रियों टिम लॉफटन और नॉर्मन बेकर को हाउस ऑफ कामन्स के स्पीकर जॉन बेरको के अपार्टमेंट में 20 जून को दलाई लामा के साथ आयोजित एक निजी भोज शुरू होने से कुछ मिनट पहले इसमें शामिल होने से रोक दिया गया। दोनों मंत्री इससे काफी भड़क गए और उन्होंने इस "गहरे शर्मिंदा" करने वाली घटना के विरोध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा।

चैनल फोर के पास इस पत्र की एक कॉपी है। श्री लॉफटन ने चैनल फोर के डिस्पैच कार्यक्रम में बताया कि पहले उन्हें और श्री बेकर को दलाई लामा के 14 जून से 23 जून के बीच ब्रिटेन के दौरे पर उनसे मिलने को मंजूरी दी गई थी। दोनों को इस भोज में शामिल होने के लिए खास वजह थीः श्री बाकर तिब्बत सोसाइटी के मानद अध्यक्ष हैं, जबकि श्री लॉफटन तिब्बती सोसाइटी कौंसिल के सदस्य हैं। श्री कैमरन के साथ चल रहे अधिकारियों के बार–बार फोन करने के बावजूद दोनों मंत्री भोज में जाने को दृढ़प्रतिज्ञ थे, लेकिन अंतिम समय में विदेश मंत्री जेरेमी ब्राउने के हस्तक्षेप के बाद उन्हें रुकना पड़ा।

खबर के मुताबिक इन दोनों मंत्रियों ने श्री कैमरन को जुलाई में ही एक पत्रक लिखकर इस पर कड़ा ऐतराज जताया कि किस तरीके से उन पर अंकुश लगाया गया। उन्होंने इस बारे में भी शिकायत की कि, "इस समारोह में शामिल न होने के लिए हम पर अंतिम मौके पर भारी दबाव बनाया गया।" उन्होंने पत्र में लिखा, "हमारे लंबे समय से तिब्बती समुदाय से संपर्क को देखते हुए इस छोटे निजी दोपहर भोज में अनुपस्थित रहना हमारे लिए काफी शर्मनाक बात थी और इस बात पर स्पीकर ने जरूर ध्यान दिया होगा जिनसे हमें काफी देर से क्षमा मांगनी पड़ी और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि दूसरे लोगों ने इस पर गौर किया होगा।"

इस पत्र की प्रति विदेश सचिव विलियम हाग और उप प्रधानमंत्री निक क्लेग को भी भेजी गई। इन दोनों महानुभावों ने कहा, "हमें लगता है कि हमें इस बारे में अपनी चिंता और पीड़ा जाहिर करनी चाहिए, जिस तरह से पिछले हफ्ते मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए गए, दलाई लामा के ब्रिटेन दौरे के दौरान उनसे किसी भी तरह का संपर्क रखने पर रोक लगा दी गई।"

दोनों मंत्रियों ने कहा कि दलाई लामा के पास अब कोई भी राजनीतिक पद नहीं है और वे खुद मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि सामान्य व्यक्ति के रूप में एक धार्मिक नेता से मुलाकात करने जा रहे थे। उन्होंने अनुभव किया कि प्रतिबंध की यह कार्रवाई "साफ तरह से गलत थी" और "इस बात के जैसी ही थी कि तिब्बत पर ब्रिटेन की विदेश नीति वैसी ही बनाई जा रही है, जैसा कि चीन इसे चाह रहा है।"

श्री लॉफटन को सितंबर में हुए फेरबदल में मंत्री पद से हटा दिया गया, जबकि यातायात मंत्री श्री बेकर अब भी अपने पोस्ट पर बने हुए हैं।

आत्मदाह को बंद करने के लिए ईयू और कनाडा ने चीन–तिब्बत वार्ता शुरू करने की मांग की

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 16 दिसंबर)

तिब्बत में मानवाधिकारों की चर्चा के किसी भी प्रयास को चीन नाराज होकर अपने आंतरिक मामलों में दखल बताता है, लेकिन अपने पक्ष पर अडिग रहते हुए ईयू और कनाडा भी तिब्बत में जारी दुःखद आत्मदाह पर चिंता जताने वालों में शामिल हो गए हैं। तिब्बत में फरवरी 2009 से अब तक कम से कम 95 आत्मदाह हो चुके हैं और इनमें से 28 आत्मदाह की घटनाएं तो अकेले नवंबर, 2012 में हो चुकी हैं। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि सुश्री

(1)

(2)

(10)

कैमरे की आंख

1 एक निर्वासित तिब्बती भिक्षु 50 वर्षीय टामडिन थार की एक तस्वीर हाथ में लिए हुए, टामडिन
लगा ली थी। (फोटो एएफपी/गेट्टी इमेज)।

2 परमपावन दलाई लामा ने 28 नवंबर, 2012 को मुंबई में विश्व करुणा दिवस पर एक व्याख्य
कपूर (दाएं से तीसरे), ह्यूमन सोसाइटी ऑफ दि यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट और सीईओ वेइ
निर्माता प्रीतीश नंदी (दाएं)। (फोटोः ओएचएचडीएल/जेरेमी रसेल)

3 फ्रांस के शहर पेरिस में तिब्बत के प्रति एकजुटता रैली में हिस्सा लेते तिब्बती और उनके फ्र

4 उत्तर भारत के शहर धर्मशाला में 17 वर्षीय भेनछेन की के प्रति शोक संवेदना जताने और उन
बैठे निर्वासित तिब्बती और उनके समर्थक। (फोटोः फायूल/नोर्बू वांग्याल)।

5 नई दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 को थाई बौद्ध विद्वानों से संवाद के दूसरे दिन थाई मठ समु
(फोटोः ओएचएचडीएल/तेनजिन छोजोर)।

6 शहीद होने वाले सभी तिब्बतियों की आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखते हु

7 दिल्ली के मजनू के टीला स्थित तिब्बती बस्ती के स्वर्णजयंती समारोह के अवसर पर 26 दिस
सांगे। (फोटोः तेनजिन निभुम/वाइल्ड तिब्बत पिक्चर्स)।

8 नई दिल्ली में 30 नवंबर, 2012 को आयोजित एक कार्यक्रम में सिक्योंग डॉ. लोबसांग सांगे
जंग (बाएं से दूसरे)।

9 दिल्ली में 10 दिसंबर, 2012 को आयोजित एक कार्यक्रम में जुटे तिब्बती और तिब्बतियों के

10 पेरिस में 10 दिसंबर को तिब्बत एकजुटता रैली को संबोधित करते फ्रांसीसी सीनेटर जीन–

(9)

(8)

(3)

(4)

(5)

...मरे की आंख से

...में लिए हुए, टामडिन ने तिब्बत में चीनी शासन के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जून, 2012 में खुद को आग

...दिवस पर एक व्याख्यान दिया। इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य लोगों में बॉलीवुड अभिनेता अनिल ...डेंट और सीईओ वेइन पसेले (दाएं से दूसरे) और जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एवं फिल्म

...तिब्बती और उनके फ्रांसीसी समर्थक।

...वेदना जताने और उनके प्रति एकजुटता दिखाने के लिए आयोजित मोमबत्ती जुलूस के दौरान घुटने के बल ...ल)।

...र दिन थाई मठ समुदाय के सदस्यों के पहुंचने पर उनका अभिवादन स्वीकार करते परमपावन दलाई लामा।

...ट का मौन रखते हुए परमपावन दलाई लामा और सिक्योंग डॉ. लोबसांग सांगे। (फोटोः ओएचएचडीएल)।

... अवसर पर 26 दिसंबर, 2012 को पहुंचे परमपावन दलाई लामा और तिब्बती राजनीतिक नेता डॉ. लोबसांग

... डॉ. लोबसांग सांगे (बाएं से तीसरे) और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति श्री नजीब

...। और तिब्बतियों के समर्थक।

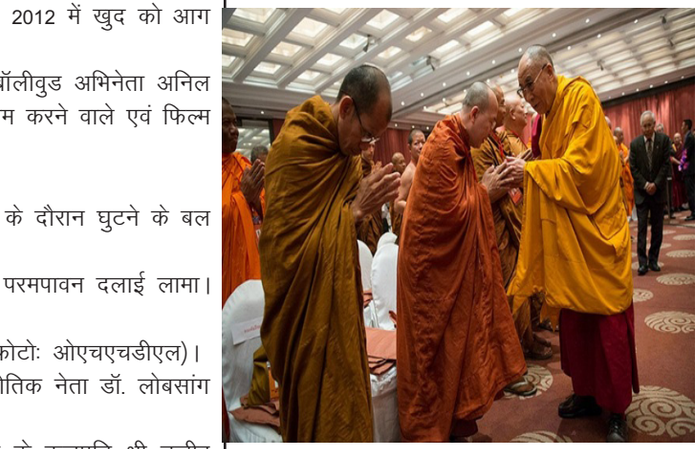

...सीसी सीनेटर जीन–फ्रैंसियस हम्बट। ***(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)***

(7)

(6)

कैथरीन एश्टन ने एक घोषणापत्र जारी कर तिब्बत में आत्मदाह की बढ़ती संख्या, खासकर बहुत से युवाओं द्वारा किए जाने वाले आत्मदाह पर गहरा दुःख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि तिब्बती पहचान की अभिव्यक्ति पर चीन द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने की वजह से ही तिब्बती इलाके में असंतोष बढ़ रहा है। घोषणापत्र में चीन से कहा गया है कि वह तिब्बती जनता की कुंठा की जड़ तलाशकर उसका समाधान करे और यह सुनिश्चित करे कि उनके नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान किया जाए ताकि तिब्बती लोग अपने धर्म का पालन कर सकें और अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकें।

इस घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त सुश्री नवी पिल्लई के 2 दिसंबर, 2012 के उस बयान का समर्थन किया गया है जिसमें उन्होंने चीन से आग्रह किया है कि वह तिब्बतियों के शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति के अधिकारों का सम्मान करे, संयम से कोई कार्रवाई करे और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के लिए हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा किया जाए। इस घोषणापत्र में कहा गया है कि तिब्बत के दुःखद हालात को खत्म करने के लिए सभी संबंधित पक्ष मिलकर एक सार्थक वार्ता करें।

ओटावा में कनाडा के विदेश मंत्री जॉन बेयर्ड ने भी चीन से आग्रह किया कि तिब्बत के मसले पर दोनों पक्षों को स्वीकार्य हल निकालने के लिए वह निर्वासित तिब्बती नेतृत्व के साथ एक सार्थक और तात्विक वार्ता करे। उन्होंने एक बयान में कहा, "मैं चीन के तिब्बती इलाके में आत्मदाह की बढ़ती संख्या से चिंतित हूं और इसकी प्रतिक्रिया में लगातार दंडात्मक कदम उठाए जा रहे हैं जिससे इस इलाके में तनाव और बढ़ रहा है।

अभिव्यक्ति, सभा करने और संघ बनाने की तिब्बतियों की स्वतंत्रता को कनाडा का समर्थन जताते हुए उन्होंने कहा, "किसी को भी यह महसूस करना चाहिए कि इस तरीके को जायज ठहराते हुए जीवन के ऐसे अंत से यह साबित हो जाता है कि तिब्बतियों में अपने धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए कितनी तड़प है।" वे चाहते हैं कि चीन इस तरीके से तिब्बती जनता की परंपराओं और संस्कृति को पूरी तरह से मान्यता दे जिससे तनाव दूर करने में मदद मिले।

ईयू घोषणापत्र और श्री बेयर्ड दोनों ने चीन से यह आग्रह किया कि वह तिब्बत के प्रभावित इलाकों में राजनयिकों, मीडिया और अन्य पर्यवेक्षकों के जाने पर लगी रोक को हटाए।

तिब्बत के भविष्य को लेकर अमेरिका ने ईयू के साथ संयुक्त रणनीति बनाने की जरूरत बताई

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 15 दिसंबर)

अमेरिकी सरकार ने 11 दिसंबर को कहा कि कई यूरोपीय सरकारें उसके इस आह्वान में शामिल हुई हैं कि चीन तिब्बत में खराब होती मानवाधिकार दशाओं को दूर करे और कहा कि यह एशिया में अमेरिका–यूरोपीय संघ के संभावित "साझे रणनीतिक वचनबद्धता" का एक उदाहरण है। वाशिंगटन डीसी में यूरोपीय संघ मानवाधिकार दिवस समारोह में पढी गई टिप्पणी में अमेरिकी अवर विदेश मंत्री और तिब्बती मामलों की विशेष समन्वयक मारिया ओटेरो ने कहा, "जर्मनी, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक और पोलैंड जैसी यूरोपीय सरकारें चीन सरकार से यह आह्वान करने में शामिल हुई हैं कि वह तिब्बती इलाके में खराब होते मानवाधिकार की स्थिति को दूर करे।" ओटेरो की तरफ से यह टिप्पणी उप सहायक विदेश मंत्री डैन बायर ने पढ़ी।

वाशिंगटन स्थित अंतरराष्ट्रीय तिब्बत अभियान (आईएसटी) की अध्यक्ष मैरी बेथ मार्के ने 13 दिसंबर को कहा, "यह वाजिब ही है कि विदेश मंत्रालय ने मानवाधिकार दिवस पर सार्वजनिक तौर पर तिब्बत के संकट पर जोर दिया है और यह संतोषजनक बात है कि इसके तिब्बत के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को यूरोपीय संघ भी एशिया में अमेरिकी और यूरोपीय हितों को आगे बढ़ाने के लिहाज से कूटनीतिक मान रहा है।"

तिब्बत में जारी संकट पर एक हफ्ते के भीतर यह अवर विदेश मंत्री ओटेरो का दूसरा बयान है। गत 6 दिसंबर को उन्होंने एक बयान जारी कर चीन से आग्रह किया था कि वह आत्मदाह की मूल वजह से निपटे। चीन ने इस बयान की कड़ी आलोचना करते हुए इसे चीन के आंतरिक मामलों में दखल देना माना था।

ड्रैगन से झुलसे लोग

(हिंदुस्तान, 13 दिसंबर, 2012)

ब्रह्मा चेलानी

चीन के भारत पर हमले की हाल में आई 50वीं वर्षगांठ (20 अक्टूबर–1 दिसंबर) ने बहुत तरह की चर्चाओं को जन्म दिया है। इससे मिले सबक चीन के अन्य पड़ोसी देशों के

लिए भी प्रासंगिक हैं क्योंकि 1962 ने चीन के युद्ध–लड़ाई के सिद्धांतों के प्रमुख तत्वों को उद्घाटित कर दिया। एक ऐसा सिद्धांत जिसे उसने 1969 में (सोवियत सेनाओं को सीमा पर टकराव के लिए उकसाने में), 1974 में (पार्सल आइसलैंड पर कब्जा करने में), 1979 में (वियतनाम पर चढ़ाई में), 1988 में (जॉनसन रीफ पर कब्जा करने में) इस्तेमाल किया। इन सभी हमलों में 1962 के बड़े तत्वों को दोहराया गया।

वर्ष 2010 में पेंटागन की एक रिपोर्ट में 1962 का हवाला देते हुए कहा गया है, "आधुनिक चीनी युद्ध के इतिहास से हमें ऐसे कई केस स्टडी मिलते हैं जिसमें चीनी नेताओं ने यह दावा किया है कि उनकी सैन्य तैयारी सामरिक दृष्टि से रक्षात्मक कार्रवाई की थी। वास्तव में 2010 में एक प्रभावी जर्नल किउ शी में लिखे आलेख में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय पार्टी के वैचारिक और सैद्धांतिक अंग ने चीन की नीति में 'आक्रमण की प्रतिरक्षा' की केंद्रीयता पर जोर देते हुए घोषणा की, "नए चीन के पूरे इतिहास में चीन में कभी भी शांति उपहार में नहीं, बल्कि युद्ध के द्वारा ही मिली है. राष्ट्रीय हितों की रक्षा कभी भी सिर्फ बातचीत से नहीं होती बल्कि युद्ध से होती है।"

भारत अब भी भोलेपन से यह मानता है कि उसे आज़ादी अहिंसा से मिली है, इसलिए नहीं कि विश्व युद्ध से थक चुका ब्रिटेन अब अपने उपनिवेशों पर और पकड़ नहीं बनाए रख सकता था। इसके विपरीत 'नए चीन' का जन्म एक लंबे गृहयुद्ध के बाद खूनखराबे के बीच हुआ था। यह खून से बना था, माओत्से तुंग और उनके साथी क्रांतिकारी आंतरिक या बाह्य स्तर पर हमेशा ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहते थे। नए चीन के स्थापित होने के कुछ समय बाद ही उसने शीक्यांग और तिब्बत को जबरन हड़प कर अपने भौगोलिक क्षेत्र को आसानी से दोगुना कर लिया। चीन में घरेलू स्तर पर गद्दारी के शक, भाई द्वारा भाई की हत्या और मानवीय विनाश से लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। वास्तव में माओ ने भारत पर तब हमला किया जब उनके 'ग्रेट लीप फॉरवर्ड' (आगे की ओर बड़ी छलांग) ने लिखित इतिहास की दुनिया के सबसे बुरे अकाल की स्थिति पैदा कर दी। चीनी विद्वान वांग जिस की के मुताबिक इसकी वजह से उनकी विश्वसनीयता को काफी नुकसान पहुंचा था। इस युद्ध ने नेतृत्व को उभार देने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन का काम किया। जी हां, जैसे एक बलात्कार पीड़ित पर यह दोषारोपण किया जाता है कि उसने ही इसके लिए उकसाया होगा, उसी तरह से हर वर्षगांठ पर भारत पर बार–बार यह आरोप लगाया जाता रहा कि उसने अपने 'उकसाने वाले' भाव और कदमों से चीन को आक्रामक बनने के लिए मजबूर किया है।

जब चीनी सेना ने सैकड़ों मील दक्षिण में कूच किया और तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो इतिहास में पहली बार समूचे हिमालय के समानांतर बड़ी संख्या में हान सेना की मौजूदगी हुई और भारतीय इलाके पर चीन के लुके–छिपे अतिक्रमण के लिए मंच तैयार हुआ। लेकिन इससे कथित तौर पर इस बात के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनता कि भारत अपने अरक्षित हिमालयी सीमाओं की रक्षा करे। इसलिए जब काफी देर से भारत ने अपने तब अव्यवस्थित रही सेना की कुछ टुकड़ियों को तैनात किया तो बीजिंग के शब्दों में यह "आगे बढ़ने वाली नीति" है और इस शब्द को कई आज्ञाकारी विश्लेषकों ने लपक लिया और अब भी इसे उछाला जाता है। भारत उस तरह से युद्ध की वर्षगांठ नहीं मनाता जैसा कि अमेरिका मनाता है। वहां हर साल होने वाले समारोह में अपने हारे हुए नायकों का सम्मान किया जाता है। उदाहरण के लिए 71 साल पहले जिस बिल्कुल ठीक समय पर जापानियों ने पर्ल हार्बर पर बमबारी शुरू की थी, उसी समय पिछले सप्ताहांत में पर्ल हार्बर और अन्य स्मारकों पर स्मृति सभाएं आयोजित की गई जिसमें हजारों अमेरिकियों ने हिस्सा लिया। दूसरी तरफ, भारत ने 1962 या किसी भी अन्य युद्ध में मारे गए सैनिकों के सम्मान में एक भी विशेष स्मारक नहीं बनाया है। इसके विपरीत चीन ने तिब्बत में 1962 के युद्ध का एक स्मारक बनाया है और उसके बीजिंग स्थित सैन्य संग्रहालय में लगी प्रदर्शनी में भारत को एक "आक्रमणकारी" के रूप में दिखाया गया है।

इस संदर्भ में भारत पर चीनी हमले की 50वीं वर्षगांठ (जिसे अमेरिकी विद्वान रॉड्रेरिक मैकफार्कुहर 'माओ का भारत युद्ध' कहते हैं) ऐसा समय होना चाहिए था जिसमें यह दिखता कि भारत ने कुछ बड़ा और स्थायी सबक सीखा है। इसकी जगह दुःखद रूप से इस अवसर पर कुछ टिप्पणीकार 1962 के बारे में मिथकों को फिर से दोहरा रहे हैं, जिसमें से एक यह भी है कि यह एक "संक्षिप्त युद्ध" है।

जबकि वास्तव में यह 1947 के बाद भारत द्वारा सामना किए गए सबसे लंबे और रक्तरंजित युद्धों में से एक था। हालांकि, युद्ध की लंबाई आमतौर पर उसके परिणाम को देखते हुए अप्रासंगिक थीः

इजराइल ने तो बुनियादी तौर पर 1967 में हुए छह दिन के युद्ध में अपने क्षेत्र के जल और भूमि के नक्शे को बदल दिया था, इसी तरह 1971 में 13 दिन के युद्ध में भारत ने

भी बांग्लादेश का नक्शा तैयार कर दिया था। 1962 का युद्ध 42 दिन तक चला था, 1965 के युद्ध (38 दिन) से भी ज्यादा। चीन द्वारा 21 नवंबर, 1962 को एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी उसके सैनिकों ने पूर्वी सीमा पर बंदूकों की कमी और संख्या में कम भारतीय सैनिकों पर फायरिंग जारी रखी। युद्ध असलियत में 1 दिसंबर को खत्म हुआ जब चीन ने अक्साई चीन पठार इलाके पर अपनी क्षेत्रीय बढ़त हासिल कर ली थी। चीन ने पूर्वी सीमा से अपने सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया क्योंकि बर्फबारी के बाद पहाड़ी दर्रों के बंद हो जाने के बाद उसके लिए समूचे मैकमोहन रेखा पर उसके सैनिकों की आवाजाही संभव नहीं थी।

इसे दुनिया के सबसे ऊंचे अक्षांश के युद्ध का दर्जा दिया गया और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहला पूर्ण युद्ध था। इस युद्ध में 3,270 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 1947–48 के युद्ध में करीब 1,100 सैनिक, 1965 में 3,264 सैनिक, श्रीलंका के ऑपरेशन पवन में 1,157 सैनिक और करगिल में 522 सैनिक मारे गए थे। इसके बावजूद मुंबई में पिछले हफ्ते आयोजित एक सेमिनार में 1962 के युद्ध को "झड़प" कहने का उतावलापन दिखाया गया।

चीन के 1962 के युद्ध के सामरिक सिद्धांत के प्रमुख तत्वों को निकाला जाए तो भारत के लिए और उन अन्य देशों के लिए भी जो चीन के साथ सीमा विवाद में उलझ चुके हैं, वास्तव में कई स्थायी सबक हैं। चीन ने अपने अगले आक्रमणों में 1962 के जिन कुछ सिद्धांतों को दोहराया है वे इस प्रकार हैं:

- ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक झटका देने के लिए विपक्षी को चकित कर दें।
- हमला तभी करें जब अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर समय इसके अनुकूल हो।
- हमले की 'मानव लहर' छोड़कर जितना संभव हो सके उतनी तेजी से और सख्ती से चोट करें।
- हमले को बचाव मानने वाले सैन्य दांव के मुखौटे को हासिल करने के लिए तैयार रहें।
- 'सबक सिखाने' के राजनीतिक उद्देश्य के साथ हमला शुरू करें, एक ऐसा उद्देश्य जिसे 1962 और 1979 के हमलों में सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया गया। नया चीन प्राचीन सिद्धांतकार सन जू की इस सलाह को गढ़ रहा है: "सभी युद्ध छल पर आधारित होते है। हमला वहां करें जहां दुश्मन तैयार न हो, सेना को तब दौड़ा दें जब ऐसा करने की आपसे अपेक्षा न की जाती हो। यह जीत के लिए सामरिकविदों की कुंजी है।"

__ब्रह्मा चेलानी__ नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सामरिक अध्ययन के प्रोफेसर हैं।

तिब्बती नेता को अब भी उम्मीद है कि कनाडा से कुछ सीखेगा चीन

(स्टीफैनी नोलेन, नई दिल्ली, 3 दिसंबर, 2012)

निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रमुख ने कहा कि तिब्बती लोगों की आज़ादी की आकांक्षा के प्रति अपनी आशंका को दूर करने के लिए चीन को कनाडा का उदाहरण देखना चाहिए। द ग्लोब ऐंड मेल को दिए एक विशेष इंटरव्यू में तिब्बती शरणार्थी और कानूनी विद्वान लोबसांग सांगे ने सतर्कता के साथ यह उम्मीद जताई कि अगले वसंत में चीन में नेतृत्व परिवर्तन के बाद तिब्बत के प्रति लगातार बढ़ती कठोर नीतियों को वापस लेने का क्रम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि वैसे तो चीन इन दिनों राष्ट्रवाद के उभार के दौर से गुजर रहा है, फिर भी उनके इस आशावाद का 'आधार' है। सांगे ने तिब्बती भिक्षुओं के आत्मदाह के रूप में सामने आ रहे चीनी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की "चरम" कार्रवाई पर भी खेद जताया। लेकिन उन्होंने कहा कि इन कार्रवाइयों से यह साफ होता है कि तिब्बतियों को किस तरह के दमन के माहौल में रहना पड़ रहा है।

सांगे को पिछले साल ही उत्तरी भारत के धर्मशाला में केंद्रित निर्वासित तिब्बती सरकार का सिक्योंग (या प्रधानमंत्री) चुना गया है। इस पद पर रहते हुए उन्होंने तिब्बती समुदाय के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी दलाई लामा से ले ली है और इस तरह अब वह तिब्बतियों के स्वायत्तता के लिए चल रहे आंदोलन के भी अगुआ हो गए हैं। उन्होंने द ग्लोब से ऐसे समय में बात किया है, जब तिब्बतियों के पहले समूह को अगले साल कनाडा आने के लिए चयनित किया गया है। कनाडा की मौजूदा सरकार भारत में रह रहे ज्यादा से ज्यादा 1000 तिब्बतियों को अगले साल कनाडा ला सकती है।

बीजिंग में एक सप्ताह पहले कम्युनिस्ट पार्टी की 18वीं कांग्रेस में स्थापित नए नेतृत्व के बारे में आप क्या सोचते हैं, और आपके हिसाब से इसका तिब्बत के लिए क्या मतलब हो सकता है?

मेरा मानना है कि इसके बारे में अभी कुछ कहना काफी जल्दबाजी होगी। वहां के सात नेताओं में से ज्यादातर 60 से 70 के बीच के हैं, इसलिए 19वीं कांग्रेस में ज्यादा थोक में बदलाव हो सकते हैं। 18वीं कांग्रेस में तो वही लोग बने हुए हैं जो 16वीं

और 17वीं कांग्रेस में थे। इसलिए आपको यदि वास्तव में बदलाव देखना है तो 19वीं कांग्रेस तक इंतजार करना पड़ेगा। इस बात की संभावना ज्यादा है कि पहले की नीति जारी रहे। खासकर इस तथ्य को देखते हुए कि कई ज्यादा ''उदार'' लोग जो युवा हैं और खुले विचार के हैं उन्हें शामिल नहीं किया गया है। मार्च में शी जिनपिंग के राष्ट्रपति पद का कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही हमें इस बारे में कुछ संकेत मिल सकते हैं। तब वह भाषण देंगे जिसमें वह अपनी सोच को दर्शाएंगे। इसके अलावा अंदाजा लगाना कठिन है क्योंकि वहां की व्यवस्था काफी अपारदर्शी है।

दलाई लामा का कहना है कि वह श्री शी जिनपिंग के बारे में आशावादी हैं, शायद इस वजह से कि उनके शी के पिता से गर्मजोशी वाले रिश्ते रहे हैं।

आशावाद बहुत मजबूत है। एक मनुष्य होने के नाते आपको हमेशा उम्मीद बननाए रखनी पड़ती है। लेकिन आशावाद का कुछ आधार होना चाहिए। शी जिनपिंग पूर्व चीनी उप प्रधानमंत्री शी झोंगशुन के बेटे हैं, जिन्होंने 1954 में बीजिंग में परमपावन का स्वागत किया था और कई बार परमपावन के साथ रह चुके हैं। परमपावन ने उन्हें एक घड़ी उपहार में दी थी जिसे उन्होंने सांस्कृतिक क्रांति और उसके बाद के दिनों में भी पहन रखा था। उन्होंने एक तस्वीर ली थी और शी झोंगशुन ने इसे संभाल कर रखा था। इसलिए ऐसा लगता है कि दलाई लामा के प्रति गर्मजोशी की भावना सही थी। शी झोंगशुन के स्वर्गीय पंचेन लामा से भी गहरे रिश्ते रहे हैं और उन्होंने उनसे कहा था, 'धैर्य रखें, नाराज न हों, हालात बदलने में समय लगता है।'

तो इस तरह के व्यक्तिगत रिश्तों का इतिहास है, क्या इससे आपको थोड़ी उम्मीद जगती है?

किसी भी नेता के लिए कोई निर्णय लेने के लिए उसे मसले से परिचित होना चाहिए क्योंकि इससे वह सही निर्णय ले सकता है और यदि आप मसले को अच्छी तरह से जानते हैं और आप उससे परिचित हैं तो उस मसले से निपटना और उसके बारे में निर्णय लेना आसान होता है।

शी जिनपिंग के पिता चीन के सबसे उदारवादी नेता हू याओबांग के समर्थक थे और उन्होंने अंतिम दम तक उनका समर्थन किया, वह हू याओबांग के साथ खड़े होने वाले अंतिम आदमी थे। इसलिए अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बेटा भी पिता की तरह होगा?

चीन के भीतर काफी कुछ काफी तेजी से घट रहा है। इस तरह का राष्ट्रवाद उभर रहा है और दक्षिण चीन सागर में सैन्य दुस्साहस बढ़ रहा है, बाजार की ताकतें चीन को एक लक्ष्य की तरफ धकेल रही है। हालांकि, सामाजिक रूप से लोग भी ज्यादा दृढ़, ज्यादा खुले और ज्यादा आज़ाद हो रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग अपनी जगह बना रहे हैं। हालांकि, राजनीतिक रूप उन्नत बनने की जगह कई तरह से वे और सीमाओं में ही बंधे हैं, खासकर तिब्बत को लेकर। उन्होंने कठोर नीतियां बनाए रखा है और कई नई कठोर नीतियां लागू की हैं–कई रुख को लेकर कुछ प्रगति हुई है, लेकिन तिब्बत पर वे पीछे की ओर ही गए हैं।

आप उनके लिए ऐसी कौन–सी योजना पेश कर सकते हैं, जिसमें आप भी जुड़े हों और बीजिंग के लिए भी यह स्वीकार्य हो?

मैं समझता हूं कि क्यूबेक एक अच्छा उदाहरण है और उत्तर में नुनावुट इसका उदाहरण हो सकता है। चीन सरकार का तर्क इस निहित शंका पर आधारित है कि यदि आप तिब्बत को कुछ दे देंगे तो वे और ज्यादा से ज्यादा की मांग करेंगे और आखिरकार बाहर निकल जाएंगे या अलग हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद आखिरकार यदि आप उस साम्य तक पहुंच जाएंगे जहां लोगों को वह मिल जाए जो वह चाहते हैं, तो बहुसंख्यक लोग यह तय करेंगे कि देश के भीतर रहना है। क्यूबेक में भी यह देखा गया है कि आज़ादी की वकालत करने वाले जुनूनी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा रही है, लेकिन वहां दो जनमत संग्रह हुए और दोनों बार लोगों ने कनाडा के साथ रहने का निश्चय किया है। इसका मतलब यह है कि बहुमत यह सोचता है कि आप साम्य तक पहुंच चुके हैं।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह एक जटिल मसला है और राष्ट्र बनाने की मांग हमेशा बनी रहेगी। तो आप इससे क्या सबक लेंगे और सहयोग बढ़ाएंगे? मैं समझता हूं कि यदि चीन सरकार तिब्बतियों को स्वायतता दे देती है तो ज्यादातर तिब्बतियों को लगेगा कि यह एक अच्छा सौदा है और वे इसके साथ रहना पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज़ादी की आवाज खत्म हो जाएगी, वे खत्म नहीं होंगे। इस संबंध में मैं समझता हूं कि कनाडा इस मामले में ऐसा उदाहरण है जिसे चीन सरकार को देखना चाहिए। क्योंकि चीन सरकार का उदाहरण तो ऐसा लगता है कि 'दमन, ज्यादा दमन और ज्यादा कठोर दमन करो और हल मिल जाएगा'। लेकिन 1950 के दशक से अब तक भी यह कारगर नहीं हुआ है।

अब आत्मदाह इस बात का साफ झलक है कि कठोर नीतियों के प्रति तिब्बती लोगों में असंतोष मजबूती से घर कर गया है। आत्मदाह करने वाले युवा पीढ़ी के होते हैं–वे दलाई लामा से कभी नहीं मिले हैं, उन्होंने उन्हें बोलते हुए कभी नहीं सुना है, वे मुझसे भी कभी नहीं मिले हैं, उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है, वे वोट दे भी नहीं सकते। लेकिन तिब्बती पहचान और तिब्बती गौरव की भावना, उनके बुनियादी आज़ादी का दृढ़ निश्चय इतना ज्यादा मजबूत है कि वे यह संदेश दे रहे हैं–'यह मेरा जो कीमती जीवन है, मैं इसलिए त्याग दूंगा ताकि बीजिंग सरकार को एक संदेश दे सकूं कि तिब्बत में जो कुछ हो रहा

है वह अस्वीकार्य है। इसलिए चीनी मॉडल तो साफतौर पर काम नहीं कर रहा है।

आत्मदाह के बारे में बात करें, जिनकी संख्या अब 85 तक पहुंच गई है, क्या आप उनको विरोध प्रदर्शन का एक वैध स्वरूप मानते हैं? क्या वे आपकी धार्मिक शिक्षाओं या आपकी तिब्बती सरकार की नीतियों से टकराते हैं?

हमने तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों से बार–बार यह अपील की है कि वे आत्मदाह जैसे चरम कदम न उठाएं क्योंकि जीवन बहुत कीमती है। लेकिन आत्मदाह न सिर्फ जारी हैं बल्कि इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो हम क्या करें? एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते–या धार्मिक न हों तो भी–आपको उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करनी होती है जिनकी मौत हुई है। एक तिब्बती के रूप में आपको उनके साथ एकजुटता भी दिखानी होगी क्योंकि वे इसे तिब्बत के लिए कर रहे हैं। इसके बाद आपको उनकी आकांक्षाओं का समर्थन करना पड़ता है, जो बहुत साफ हैंः परमपावन दलाई लामा की तिब्बत में वापसी और तिब्बती जनता के लिए आज़ादी। हम कहते हैं कि 'जीवन को बचाकर रहना बेहतर है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं'। यह हमारे लिए तरजीही विकल्प होगा। लेकिन हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह विरोध प्रदर्शन का वैध तरीका नहीं है, क्योंकि आत्मदाह विरोध प्रदर्शन के एक स्वरूप के रूप में दुनिया भर में होता रहा है। ऐसा वियतनाम युद्ध के दौरान भिक्षुओं ने किया था, 1969 में चेकोस्लोवाकिया में ऐसा हुआ था और इसके बाद अरब स्प्रिंग आंदोलन के दौरान ट्यूनिशिया के एक व्यक्ति द्वारा किया गया। तिब्बत में इसका एक और अध्याय देखा जा रहा है। लेकिन यह विरोध का दुःखद रूप है और यह विरोध की सबसे हताशाजनक कार्रवाई है क्योंकि तिब्बतियों को कोई विकल्प नहीं दिया जा रहा है या विरोध के किसी भी स्वरूप की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि चीन सरकार उनको सड़कों पर आने की इजाजत नहीं देती। यदि आप कोई नारा लगाते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यदि आप दलाई लामा की तस्वीर रखते हैं तो आप जेल चले जाएंगे। यदि वे मेरी तस्वीर रखते हैं तो प्रताड़ित किए जाने की पूरी सभावना है। ऐसे माहौल में वे कह रहे हैं कि जब गिरफ्तार होने, प्रताड़ित किए जाने और गायब कर दिए जाने की संभावना ज्यादा है तो आत्महत्या कर लेना ही ठीक है।

चीन यदि आपको तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों को कोई संदेश देने का मौका दे तो आप क्या कहेंगे?

मैं यही कहना चाहूंगा कि हम अहिंसा और लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये हमारे लिए ऐसे सिद्धांत है जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता। उनकी शिकायतें वाजिब हैं, क्योंकि वे लोग पीड़ित हैं। चीन सरकार को उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए और इस मसले का जितना जल्दी हो सके समाधान करे। मैंने पहले कहा है, "तिब्बत काफी पुरानी सभ्यता है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, और एक धर्म के रूप में बौद्ध धर्म काफी समृद्ध है, और तिब्बत में महान राजाओं का बहुत समृद्ध इतिहास है। इसलिए हमें अपने ऊपर गर्व करना होगा। और इस वास्तव में बदलती दुनिया में जब सवाल उठ सकते हैं, तो सबसे पहले किसी को खुद से ही सवाल करने चाहिए। निश्चित रूप से हमारा दिन आएगा।

क्या आपने कनाडा सरकार से बातचीत की है?

मैं जैसन केन्नी (नागरिकता और अप्रवास मंत्री) से मिला। इसके अलावा अपने स्वागत भोज में गया था और वहां उपस्थित लोगों का समूह आश्चर्यजनक था। वहां ताइवानी, वियतनामी, भारतीय और तिब्बती थे (उन्होंने एक कमरे में मौजूद इन सभी लोगों से बात की)। मैं समझता हूं कि यह कनाडा में ही हो सकता है! जहां कहीं भी आप तिब्बतियों से बात करते हैं आप चीनियों का उल्लेख नहीं करते, आप चीनियों से बात करते हैं तो ताइवान का उल्लेख नहीं करते और वहां तो यह हो रहा था, 'यह है चीन पर हमारी नीति, यह आपके लिए अच्छी है', इस पर खूब तालियां बजती हैं, 'हमने ताइवान में यह किया है, यह आपके लिए अच्छा है' और 'मैं तिब्बत के अपने अच्छे दोस्तों को मान्यता देना पसंद करूंगा। तथ्य यह है कि वह इन सभी समूहों को एक कमरे में लेकर आए और उन्हें एक–दूसरे की तारीफ करना संभव बनाया, जबकि बाहर वे विरोध संगठनों के अलग–अलग पक्ष में होते हैं। उन्होंने सभी सही चीजें कहीं और उन्होंने उनसे सभी बातें कहीं।

उनकी सरकार ने अपनी विदेश नीति का केंद्र नए सिरे से तय करते हुए मानवाधिकारों से व्यापार एवं आर्थिक हितों की ओर मोड़ दिया है। यदि आप फिर से श्री केन्नी को देखते हैं या प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर से मुलाकात करते हैं तो क्या आप उनसे इस बारे में बात करेंगे?

मैं इसका विवरण नहीं जानता, लेकिन हमारा यह मानना है कि आर्थिक अधिकार तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मानवाधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अमर्त्य सेन का तर्क हैः मानव की तरक्की के बिना आर्थिक तरक्की का क्या मतलब है? मानवाधिकार अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे हैं, इसलिए उनको बचाने पर आर्थिक अधिकारों से भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

दलाई लामा का यदि निधन हो जाता है और चीन यह घोषणा कर देता है कि उसने उनका उत्तराधिकारी तलाश लिया है और उन्होंने उसे स्थापित कर दिया है तो आप क्या करेंगे?

सबसे पहले तो यह सब सोचना ही काफी जल्दबाजी है, क्योंकि परमपावन काफी स्वस्थ हैं, वह लगातार यात्रा कर रहे हैं और उनमें 35–40 साल के आदमी से भी ज्यादा ताकत है। इस सवाल पर उन्होंने सितंबर, 2011 में एक बयान जारी किया, जब सभी शीर्ष नेता धार्मिक नेता आए थे। उन्होंने कहा थाः इसके लिए (नए दलाई लामा के नाम तय करने के) तीन तरीके हैंः पुनर्जन्म जो उनके निधन के बाद फिर से जन्म लेना है। दूसरा, चयन जिसमें शीर्ष बौद्ध नेता जुटते हैं और चयन करते हैं जैसे कि पोप का चयन होता है। और तीसरा निर्गम जिसमें वह खुद अपने निधन से पहले अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करके जाते हैं। इसलिए ये तीनों विकल्प सामने हैं। लेकिन कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीन क्या करता है। आस्था दिल और दिमाग का मामला है, आप इसे खरीद नहीं सकते और इसे लोगों पर थोप नहीं सकते, आप यह नहीं कह सकते 'यह वह बच्चा है जिसमें आपको कल से भरोसा करना होगा, उसका अनुसरण करना होगा और आपको आध्यात्मिक आशीर्वाद मिलेगा'। इसके अलावा परमपावन ने खुद कहा है कि बीजिंग की कोई विश्वसनीयता नहीं है, इसलिए यदि वे पुनर्जन्म को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें पहले माओ त्से तुंग, झू एनलाई, देंग जियोपिंग का पुनर्जन्म तलाशना चाहिए क्योंकि उनका चीन के लिए काफी योगदान है।

लेकिन क्या इससे आपके सरकार के असर पर जोखिम की संभावना नहीं दिख रही–तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों तक आपके के बारे में सूचना नहीं पहुंच पाएगी और उनसे कहा जा सकता है यही नए दलाई लामा हैं.

यह सवाल तो हमेशा रहा है कि किस पर भरोसा किया जाएगा? यहां तक कि कब्जे के 50 साल बाद भी चीन सरकार तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों पर बहुत ज्यादा धन खर्च कर रही है और बहुत ज्यादा दुष्प्रचार कर रही है। जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वे पूरी तरह से चीनी व्यवस्था के तहत रहे हैं–वे अब विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वहां बुनियादी रूप से कुछ गलत है। हमारा जोश उतना ही पूरा है जितना की चीनियों का और उन्होंने हमारे बारे में कुछ कहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनकी बात मान लेंगे। सच तो यह है कि हम उनकी बात नहीं मानने वाले। हमारे समझौते का आधार स्वैच्छिक और परस्पर स्वीकार्य प्रकृति का होना चाहिए।

भारतीय जनता तिब्बत के साथ

अटल बिहारी वाजपेयी

(लोकसभा में 4 सितंबर 1959 को दिया भाषण)

तिब्बत की समस्या हमारे सामने है। पहली बार जब तिब्बत का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ में उठा तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे प्रतिनिधि ने उस समय आशा प्रकट की थी कि तिब्बत की समस्या शांति के साथ चीन से वार्ता द्वारा हल हो जायेगी, लेकिन पिछले नौ साल का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि तिब्बत की समस्या को शांति से हल करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

चीन ने तिब्बत में बल प्रयोग किया। चीन ने तिब्बत के स्वतंत्र अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की। मैंने कहा था कि आज प्रश्न केवल तिब्बत की स्वायत्तता का या स्वतंत्रता का नहीं है। बल्कि प्रश्न यह है कि क्या तिब्बत एक पृथक देश के नाते, अपनी सम्पूर्ण विशेषताओं के साथ जीवित रहेगा ? यदि भारत सरकार की यह आशा, कि तिब्बत का प्रश्न शांति से हल होगा, पूरी हो जाती तो भारत को और सदन को बड़ी प्रसन्नता होती। लेकिन अभी तक के जो आसार दिखायी देते हैं उनसे इस बात की आशा नहीं है कि आपस की वार्ता द्वारा अब इसको हल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में इस तरह की कोई आशा प्रकट नहीं की है। हमने दलाई लामा को और उनके साथियों को भारत में स्थान दिया, बहुत काम किया और सब इसका स्वागत करते हैं। किन्तु क्या दलाई लामा को आश्रय देने के साथ ही तिब्बत के सम्बन्ध में भारत का कर्तव्य पूरा हो जाता है? क्या दलाई लामा और उनके साथी कभी सम्मान के साथ तिब्बत वापस लौट सकेंगे ? क्या तिब्बत की स्वायत्तता, जिसकी चीन ने गारंटी दी थी, फिर से वापस आ सकेगी ? क्या तिब्बत अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकेगा ? इस प्रश्नों को कोई उत्तर नहीं दिया गया।

प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उनकी नीति चीन के साथ मित्रता रखने की है। उनकी इस नीति से सारा देश सहमत है। चीन से क्या, हम पाकिस्तान से भी मित्रता चाहते हैं। दुनिया के सारे देशों से दोस्ती चाहते हैं, किंतु सवाल यह है उस मित्रता का आधार क्या होगा ? किस कीमत पर वह दोस्ती की जाएगी ? हम फ्रांस से दोस्ती चाहते हैं मगर इसलिए हम अल्जीरिया की आजादी का समर्थन करने से इन्कार नहीं कर सकते। हम पुर्तगाल से भी दोस्ती चाहते हैं मगर इसके लिए हम गोवा की स्वतंत्रता की मांग को बन्द नहीं कर सकते।

मैंने जब तिब्बत के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्रसंघ में ले जाने का प्रस्ताव किया तो मेरा उद्देश्य स्पष्ट था कि हम संयुक्त राष्ट्रसंघ में विश्वास करते हैं इसलिए हमें तिब्बत के सवाल को वहां ले जाना चाहिए। और तिब्बत के शिकायत के औचित्य में भी हम विश्वास करते है, इसलिए भी हमें तिब्बत के सवाल को वहां ले जाना चाहिए।

अब तिब्बत के सवाल को वहां ले जाने से फायदा होगा या नहीं होगा, मैं समझता हूं कि इसका निर्णय अगर हम न करें और तिब्बत के सर्वोच्च नेता श्री दलाई लामा के फैसले के अनुसार चलें तो ज्यादा अच्छा होगा। तिब्बत का भला किसमें

है, क्या श्री दलाई लामा से अधिक और कोई इस बात का फैसला कर सकता है ? और उन श्री दलाई लामा ने 30 अगस्त को अपील की है दुनिया के सभी सिविलाइज्ड देश के नाम, जिनमें भारत भी आता है, कि तिब्बत के सवाल को संयुक्त राष्ट्रसंघ में ले जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अब मेरे प्रस्ताव को मानने से इन्कार करते हैं तो वह श्री दलाई लामा की अपील को मानने से भी इन्कार करते हैं। अगर श्री दलाई लामा समझते हैं कि तिब्बत की समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने से कुछ लाभ होगा तो मैं समझता हूं कि भारत को उस प्रश्न को उठाना चाहिए।

प्रधानमंत्री जी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि अगर और कोई देश तिब्बत के सवाल को संयुक्त राष्ट्रसंघ में लाएगा तो उस समय हमारी नीति क्या होगी। हम दुनिया के और किसी देश को यह सवाल लाने से नहीं रोक सकते। क्या हम उस समय यह कहेंगे कि यह सवाल नहीं लाया जाना चाहिए ? इस सम्बन्ध में हमारा जो प्रतिनितिमंडल जनरल असेम्बली में भाग लेने जा रहा है उसको स्पष्ट निर्देश देना चाहिए। मुझे संदेह होता है कि हमारे प्रतिनिधिमंडल के जो नेता असेम्बली में भाग लेने जा रहे हैं वे वहां भारत की भावनाओं का सही प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। एक बार पहले भी वे हंगरी के सवाल पर भारत की जनता की भावनाओं को सही रूप से प्रकट नहीं कर सके थे। प्रधानमंत्री कुछ कहते थे और हमारे प्रतिनिधि ा मंडल के नेता कुछ कहते थे। मुझे डर है कि तिब्बत के सवाल पर यह इतिहास न दुहराया जाए। इसलिए अगर भारत सरकार स्वयं तिब्बत के प्रश्नों को नहीं उठाती है तो जैसा कि कांग्रेस के सदस्य डॉ0 गोहोकर ने संशोधन रखा है, अगर कोई और देश इस प्रश्न को उठाता है तो भारत को उसका समर्थन करना चाहिए। पिछली बार हमने समर्थन नहीं किया इसलिए दुनिया का कोई भी देश आगे नहीं बढ़ा। आखिर तिब्बत में हमारी सबसे अधिक रूचि है, हम तिब्बत से सबसे अधिक सहानुभूति रखते हैं, तिब्बत हमारा पड़ोसी देश है।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर तिब्बत के सवाल को किसी और देश ने उठाया तो भारत की नीति क्या होगी ? मैं यह जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसके सम्बन्ध में सरकार का क्या मत है ? वह मेरा संशोधन नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने उस सम्बन्ध में सरकार के दृष्टिकोण का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया हैं।

तिब्बत के सवाल पर व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, यह ठीक है, लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंघ में ले जाने के अलावा तिब्बत की समस्या का और कोई हल दिखायी नहीं देता। वहां गरमागरम भाषण होंगे, यह ठीक है। लेकिन अगर हम संयुक्त राष्ट्रसंघ में विश्वास करते हैं और चीन संयुक्त राष्ट्रसंघ में जाना चाहता है, तो फिर विश्व के जनमत का चीन पर जरूर कुछ प्रभाव होना चाहिए। अब भारत के सामने एक ही रास्ता है कि हम विश्व की आत्मा से अपील करें, हम विश्व की चेतना को जगाएं। तिब्बत में होने वाले मानव अधिकारों के हनन के प्रति विश्व के जनमत को जाग्रत करें। और यदि कम्युनिश्चीन के भारत पर हमले की हाल में आई 50वीं वर्षगांठ (20 अक्टूबर–1 दिसंबर) ने बहुत तरह की चर्चाओं को जन्म दिया है। इससे मिले सबक चीन के अन्य पड़ोसी देशों के लिए भी प्रासंगिक हैं क्योंकि 1962 ने चीन के युद्ध–लड़ाई के सिद्धांतों के प्रमुख तत्वों को उद्घाटित कर दिया।

हम जानना चाहते हैं कि भारत सरकार की तिब्बत के प्रति नीति क्या है ? क्या हाथ पर हाथ रखे रहने की नीति है? क्या अनिश्चय की नीति है, असहायता की नीति है ? आखिर तिब्बत की समस्या को शांतिपूर्वक हल करने के लिए हम कौन–सा कदम उठा रहे हैं ? दलाई लामा को जगह देने मात्र से तिब्बत की समस्या हल नहीं होती।

अभी भारत ने फैसला किया है कि हम चीन को संयुक्त राष्ट्रसंघ में लाने के प्रस्ताव को इस बार फिर से उठायेंगे। मैं समझता हूँ कि समय आ गया है कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्रसंघ में चीन को प्रवेश दिलाने के प्रस्ताव को ड्राप कर दे। अगर दुनिया का कोई भी देश उस सवाल को उठाए तो हम उसका समर्थन कर दें। यदि हम तिब्बत के सवाल को उठाने को तैयार नहीं तो फिर चीन जो कुछ हमारे साथ रहा है उसका देखते हुए चीन को संयुक्त राष्ट्रसंघ में प्रवेश दिलाने के लिए पहल क्यों करें ? चीन से मित्रता का यह अर्थ नहीं है कि वे लात मारते जाएं और हम उनके चरणों को चूमते जाएं। मित्रता आत्मसम्मान के आधार पर हो सकती है। चीन आक्रमणकारी है, चीन हमारी सीमा पर प्रवेश करने आया है। हमारे दरवाजे खटखटा रहा है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम सीमा के सम्बन्ध में बात करने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि हमें अब चीन के सवाल को उठाना नहीं चाहिए।

मैं इस सदन से अपील करूंगा कि वह मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करे और यह सिद्ध करें कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय कठिनाइयों से भारत तिब्बत के सवाल को भले ही न उठा सके, मगर भारत की जनता की भावनाएं तिब्बत की जनता के साथ है, दलाई लामा के साथ हैं।